GEOGRAPHY

01

(8) भारत मे पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए निर्मित योजना का परीक्षण कीजिए।

Ans => भारत का लगभग 17% क्षेत्र पहाड़ी है जहाँ देश की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। मोटे तौर पर ऐसे क्षेत्र को दो भाग मे बाँटा गया है- (i) वे जो सम्पूर्ण राज्य का निर्माण करते है। एवं (ii) वे जो किसी राज्य के भाग है। प्रथम वर्ग मे उत्तर पूर्व के राज्य जम्मू एवं कश्मीर हिमाचल प्रदेश, एवं उत्तराखंड सम्मिलित है ये विशिष्ट श्रेणी के राज्य कहलाता है। इनके खर्च का बड़ा भाग केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरा किया जाता है। उत्तर पूर्वी के राज्यो के समन्वित विकास हेतु संसद अधिनियम (1971) द्वारा उत्तर-पूर्वी परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद ने ऊर्जा उत्पादन, परिवहण, सड़क निर्माण, कृषि, पशु-पालन मात्स्यिकी आदि के अंतर्प्रादेशिक कार्यक्रमो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

द्वितीय वर्ग के अंतर्गत असम के कार्बी, आंगलोंग, एवं उत्तरी कछार जिले और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के भाग शामिल है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा एवं केरल में पाया जाता है। यद्यपि इनके विकास की जिम्मेदार सम्बन्धित राज्यो का है परंतु केन्द्र सरकार द्वारा अलग से वित्तीय सहायता किया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्र की समस्याएँ मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है। यही कारण है कि इनकी

2020-8-8 21

स्थलाकृतिक और सामाजिक आर्थिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र हेतु अलग-अलग विकास योजनाओं को बनाने की जरूरत है। इसमें सम्बन्धित क्षेत्र के भूमि, खनिज, जल एवं जैविक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण विकास नीति स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता पर आधारित होना चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में बागवानी, बगान, कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, वानिकी, मृदा संरक्षण एवं ग्रामीण उद्योग पर बल दिया जाता है। इसमें कार्यक्रमों के पैकेज एवं ग्रामीण उद्योग पर बल दिया जाता है। उदाहरणार्थ वानिकी कार्यक्रमों में बगाती कृषि, कहवा, चाय, मसाला आदि कृषि वानिकी या बागवानी में फलोद्यान सेब, अंगुर, केला आदि के साथ-साथ उनके विपणन को शामिल कर श्रेयस्कर होता है।

संबंधित क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग द्वारा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम में निम्न क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाता है।

(i) कृषि- स्थानांतरण, स्थानबद्ध, पौधारोपण जैसे- चाय, मसाले, रबड़, अनन्नास, नारियल इत्यादि।

(ii) फलोत्पादन पर केला, सेब, अंगूर और नींबू वंश के फल।

(iii) पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, रेशम

कीट पालन और सूअरपालन को प्रोत्साहन।

(iv) मृदा संरक्षण

(v) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन

(vi) ग्रामीण युवाओं को रोजगार की उपलब्धि कराना।

(vii) सहकारिता एवं किसान सेवा सभाओं का मजबूतीकरण।

(viii) उन पहाड़ी क्षेत्रों जहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र है। विशेष कार्यक्रम द्वारा झूम कृषि को नियंत्रित करने का प्रयास करना।

कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा झूम कृषि की जाती है जिसे स्थाई कृषि में बदलने एवं झुमिया कृषिकों को पुनर्वासित करने हेतु अनेक कार्यक्रम बनाये गये हैं जिनमें कहवा, रबड़ आदि बगानों को विकसित कर झुमिया किसानों को इनका स्वामित्व सौंपना एक कारगर समाधान हो सकता है।

पशुपालन कार्यक्रम पशुओं और चरागाहों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर बनाये जाने चाहिए जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि से प्रजनन पशु स्वास्थ्य तथा पशु उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन पर बल दिया जाना चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्र ऐसे उद्योगों के लिए उपयुक्त होते हैं जिनके लिए प्रदूषण रहित पर्यावरण, शीत जलवायु, उच्च दक्षता एवं मूल्य अभिवृद्धि की आवश्यकता होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक घड़ी निर्माण, औषधी निर्माण, ऑप्टिकल ग्लास आदि प्रमुख हैं। कुटीर उद्योग के तौर ग... 2020-8-8 21:1

हथकरघा उद्योग इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही साथ इन क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर हिमालय क्षेत्र, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है यहाँ औषधीय पौधों, फलों, फूलों एवं वन्य जीवों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है अतएव यहाँ की मूल्यवान पादप एवं प्राणि संपदा के संरक्षण एवं परिवर्द्धन हेतु जैव-आरक्षित क्षेत्रों सक्रीय उद्यानों और जीन बिन केन्द्रों को स्थापित करने की जरूरत है।

पर्वतीय क्षेत्रों के वैज्ञानिक नियोजन हेतु संसाधनों मृदा, खनिज, बनस्पति, जल आदि के बारे में विधिवत जानकारी आवश्यक है जिसके लिए दूरसंवेदी तकनीक, हवाई छायाचित्र और धरातलीय सर्वेक्षण का सहारा लिया जा सकता है यहाँ क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय एवं सूक्ष्मस्तर पर अल्प-कालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें पर्यावरण सुरक्षा और जनता की सहभागिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परियोजनाओं को लगाते समय उनके पारिस्थितिक पुनरुद्धार की लागत का आकलन आवश्यक है।

=> उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के लिए वितमंत्री का 500 करोड़ का पैकेज :- वित मंत्री पी० चिदम्बरम् ने अपने बजट भाषण में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्रालय के अंतगर्त सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि से 500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी।

2020-8-8 21:

वित्तमंत्री के 2008-09 के बजट भाषण का सार निम्नवत हैं:-

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र विशेष ध्यान और बढ़ा हुआ आवंटन प्राप्त करते रहेंगे इसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए 1455 करोड़ रुपय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। विभिन्न मंत्रालयों से मिलनेवाली धनराशि को मिलाकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन वर्ष 2007-08 के 14,365 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 16447 करोड़ रुपय हो जाएगा।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और सीमावर्ती क्षेत्र विशेष समस्याओं का सामना करते हैं। जिन्हें सामान्य स्कीमों अथवा प्रचलित पद्धति से हल नही किया जा सकता इसलिए सरकार इन क्षेत्रों की तात्कालिक आवश्यकताओं का पता लगाती है उसके बाद समस्याओं का हल निकालने का प्रस्ताव करती है केन्द्र सरकार ने समय-समय पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेजों की घोषणा करती है जो निम्नलिखित है

S.No.	Scheme/Project	Ministry/Department	Comments
1.	सामाजिक अप-संरचना विकास विकास निधि से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री का 500 करोड़ रुपय का प्रावधान 2008-9 के बजट में घोषित	डोनर मंत्रालय	ब्यौरा

2020-8-

2.	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद पैकेज	डोनर मंत्रालय	ब्यौरा
3.	उत्तर पूर्वी असम राज्यों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज	डोनर मंत्रालय	ब्यौरा
4.	उत्तर पूर्वी के लिए त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	ब्यौरा
5.	उत्तर-पूर्वी सवाय रेल विकास निधि	रेल मंत्रालय	उ० पूर्वी क्षेत्र की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अव्ययपगत रेल विकास निधि इस योजना में 25% रेल मंत्रालय तथा 75% वित्त मंत्रालय के सहायता से कार्य पूरा होगा।
6.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम प्रबंध प्रकोष्ठ	जैव प्रद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	—
7.	उत्तर पूर्वी और हिमालयन राज्यो के लिए उद्यान कृषि मिशन	कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय	उद्यान कृषि मिशन में 4 मिनी मिशन शामिल है— (i) उच्चकोटी के बीजों, रोपण, सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति करना (ii) उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार (iii) फसल के बाद प्रबंधन विपणन (iv) मिनी मिशन

6.	अरुणाचल प्रदेश और चांगलांग जिले के लिए विशेष बोर्ड	गोंडवाना श्रेणी	—
7.	विनिक्रम रचित उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए पूर्वोत्तरीय एवं परिवहन सेक्टर के लिए केन्द्रीय	महासागरों मंत्रालय	

=> ऊपरी गोंडवाना क्रम :-

-> महादेव उपक्रम :- सतपुड़ा श्रेणी के पहाड़ी को महादेव उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रमुखतः स्थूलसंस्तरित बलुआ पत्थर एवं शैल से निर्मित है इसमें कोयला का अभाव पाया जाता है। इसमें लाल चीका एवं बलुआ पत्थर के कुछ स्तर पाए जाते हैं

-> राजमहल उपक्रम :- इसके दो अवस्थाएँ हैं राजमहल अवस्था एवं कोटा अवस्था। इसमें राजमहल 600m मोटी स्तरित बेसाल्ट और डोलेराइट से निर्मित है। कोटा अवस्था की मोटाई 610m है इसमें चूना पत्थर की परतें पाई जाती हैं।

-> जबलपुर उपक्रम :- इस उपक्रम का विकास मुख्यतः सतपुड़ा एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ है यह उपक्रम गोलाश्म संगुटिका रचित चूना पत्थर चिकनी मिट्टी एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके निर्माण

2020-8-8

मे निक्षाइट, कोयला एवं चूना पत्थर के शैल जैसा है।

→ उमिया उपक्रम :- इस उपक्रम का नाम गुजरात के उमिया ग्राम के आधार पर किया गया है। यह आगरीय संगुटिका, बलुआ पत्थर एवं शैल का 900m मोटा उपक्रम है।

→ पूर्वी तट के गोंडवाना :- गोंडवाना के कुछ हस्यांश कोरोमण्डल तट के क्षेत्र में पाया जाता है। गोदावरी डेल्टा का निर्माण त्रपंदी बलुआ पत्थर दक्षिणी कृष्णा लाल बलुआ पत्थर, मद्रास हस्यांश सफेद शैल से निर्मित है।

⇒ दक्कन ट्रैप :- क्रिटेशस काल के अंतिम चरण में प्रायद्वीपीय भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ज्वालामुखी क्रिया से प्रभावित हुआ यह धरातल पर हजारों मीटर मोटी परत के रूप में बिछ गये थे इसे ही दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दक्कन ट्रैप का मुम्बई के पास 3000m मोटा परत पाया जाता है जबकि अमरकंटक के पास 150m तथा बेलगाम के पास 60m मोटी परत पायी जाती है। मुसावल के पास वेधन (boring) क्रिया के द्वारा 29 लावा प्रवाहों का पता चला है।
यहा पर लावा का दरारी उद्गार था जिसमें प्रचण्डता का अभाव पाया जाता है। दक्कन ट्रैप का सर्वसामान्य चट्टान औजाइट बेसाल्ट है जिसका आपेक्षिक घनत्व 2.9 है। इसका प्रमुख रंग भूरा-हरा है।

बेसाल्ट के अपघटन से काली, गहरी भूरी

या लाल रंग की रेतड़ मिट्टी का निर्माण होता है

दक्कन ट्रैप को डी. एन. वाडिया महोदय ने तीन प्रमुख खण्ड में विभाजित किया है।

(i) निचला ट्रैप:- यह 150m मोटी तह है यह इसके विषम बि-न्यास द्वारा अमेरा एवं बाघ स्तरों से पृथक किया जाता है इस क्षेत्र का विस्तार मध्यप्रदेश, नर्मदा एवं बरार के क्षेत्र में पाया जाता है।

(ii) मध्यवर्ती ट्रैप: — यह मालवा एवं मध्य भारत के क्षेत्रों पर फैला हुआ है इस भाग का निर्माण लावा एवं राख की मोटी परतों से हुई है। इसमें जीवाश्मयुक्त स्तरों का अभाव पाया जाता है यह 1200m मोटी परत है।

(iii) ऊपरी ट्रैप:- इस ट्रैप की मोटाई 450m है। इसका फैलाव महाराष्ट्र एवं सौराष्ट्र क्षेत्रों में है यह ट्रैप जीवाश्मों से सम्पन्न है।